

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ खंडपीठ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1975/2026**

करन गुप्ता उर्फ अमन गुप्ता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार राव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, श्री कार्तिक विश्वकर्मा, श्री करुणेश सिंह

न्यायालय संख्या 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

दिनांक 27.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. आवेदकों के अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. पक्षकारों के अधिवक्ता का कथन है कि पक्षकारों के मध्य वाद में समझौता हो गया है और समझौता विलेख अनुलग्नक संख्या-4 के रूप में अभिलेख पर है।

3. उक्त कथन के दृष्टिगत, पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 17.03.2026 को इसके सत्यापन हेतु समझौता विलेख के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा आगामी तिथि तक इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

4. विचारण न्यायालय की रिपोर्ट के साथ दिनांक 30.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

5. मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के समक्ष इसके सत्यापन हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने पर, अभिलेख पर इसकी एक प्रतिलिपि सुरक्षित रखते हुए आवेदकों के अधिवक्ता को वापस कर दिया जाए।

6. सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक, पुलिस थाना-महानगर, जिला-लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2024 के अनुसरण में आवेदकगण के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। "

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2026 की सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.01.2026 का समझौता विलेख सम्यक रूप से सत्यापित कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने पुलिस थाना-महानगर, जिला-लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 0120/2024 (राज्य बनाम करन गुप्ता), अंतर्गत धारा 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता में दाखिल आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा आरंभ एवं विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई., ए.पी.), लखनऊ, जिला-लखनऊ के न्यायालय में लंबित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा साथ ही साथ पारित समन आदेश दिनांक 30.07.2025 पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि कुछ भ्रान्ति के कारण, आवेदक के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, पक्षकार एक साथ बैठे और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों को सुलझा लिया है, जिसे दिनांक 09.01.2026 को लिखित रूप में दर्ज किया गया है। तत्पश्चात, आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 1975/2026 प्रस्तुत किया जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और उसके अनुपालन में, समझौता विलेख दिनांक 26.03.2026 को सत्यापित किया गया। उनका निवेदन है कि अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है। उनका निवेदन है कि वर्तमान वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए, आवेदक के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त निवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 09.01.2026 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते को दिनांक 26.03.2026 को सत्यापित कर लिया गया है तथा अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के कथन के अनुसार, वे आवेदक के विरुद्ध पूर्वोक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि आवेदक और विपक्षियों ने दिनांक 09.01.2026 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है, अतः पूर्वोक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एस.सी.सी. 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एस.सी.सी. 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303; और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466 में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार, पुलिस थाना-महानगर, जिला-लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट/वाद अपराध संख्या 0120/2024 (राज्य बनाम करन गुप्ता), अंतर्गत धारा 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता में दाखिल आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा आरंभ एवं विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई., ए.पी.), लखनऊ, जिला-लखनऊ के न्यायालय में लंबित, आवेदक के विरुद्ध संस्थित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा साथ ही साथ पारित समन आदेश दिनांक 30.07.2025 एतद्वारा निरस्त की जाती है।

यह समझौता इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार आवेदन को **स्वीकार** किया जाता है।

दाखिल दफ्तर किया जाए।

30 मार्च, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।